

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2019 (उदयपुर डिक्री)

1. शंकरलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. उंकारलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. गणेशलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. इन्द्रलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. भेरूलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. गंगाराम पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. हीरालाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. श्रीमती कंकू पुत्री स्व. पेमा कुम्हार पत्नी नारायण, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा
9. श्रीमती नोजी पुत्री स्व. पेमा कुम्हार पत्नी रतन, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पॉन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री
 उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 25/2012 दिनांक 17.07.2019

---/---

- उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अजय सनाढ्य अभिभाषक अपीलान्तगण
 2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

---:---

निर्णय

दिनांक 23-01-2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्त के पिता पेमा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 36 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सन् 1976 में जरिये पत्रावली संख्या 8/76 आवंटन सन् 1976 से मौजा कानपुर की भूमि नसबन्दी योजना के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14-10-76 को वादी द्वारा पेश किया गया, जिसे तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 17-09-1977 को वादी के पक्ष में साबिक आराजी नंबर 2531 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1085 दिनांक 29-04-1977 से भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गयी, जिसका अमल दरामद खेवट में 615 पर किया गया था, जिसका प्रमाणीकरण



तहसीलदार द्वारा भी किया गया। तब से वादी उक्त भूमि का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त साबिक आराजी के नये नंबर 5096 रकबा 1.6000 बने। इसके बाद आराजी नंबर 5096 के नये नंबर 13968/5096 रकबा 0.8650 हैक्टर बने तथा 5096 मीन रकबा 0.7350 हैक्टर बने, जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु भू-प्रबन्ध के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा पालना नहीं की गयी है तथा भूमि पुनः बिलानाम दर्ज कर दी गयी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 5096 मीन रकबा 0.7350 हैक्टर, जिस पर वादी का कब्जा है, का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार इन्द्राज दुरस्ती की जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 17-07-2019 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15-10-2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे वह समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। दिनांक 23-09-2019 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेन्ट को तलब किया गया, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। वकील अपीलान्त की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा तनकियों को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराये जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने फौरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जबकि विधि अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। रेस्पॉन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे वादी/अपीलान्ट द्वारा वाद में किये गये कथनों का खण्डन नहीं हुआ है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1983 लाधी बनाम भूराराम, आर.आर.डी. 1985 पेज 33, आर.आर.डी. 1998 पेज 261, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 451, आर.एल.डब्ल्यू. 2001 (1) पेज 600, सिविल टाईम्स (राज.) 2001 पेज 60, आर.बी.जे. 1996 (3) पेज 8, आर.बी.जे. 2004 (11) पेज 66, आर.बी.जे. 2006 (13) पेज 205, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 340, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 285, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 244 आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1080 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। वादी को विवादित भूमि आवंटित होकर उसे गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार आवंटन शर्तों की पालना किये जाने पर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। अपीलान्ट/वादी ने न तो तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है,

जिससे यह साबित हो सके कि उनके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गयी हो। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नज़ीरें वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्या नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17-07-2019 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23-01-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास अनीता मीना, आर.ए.एस.

शंकरलाल पिता स्व. पेमा कुम्हार, बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, गिर्वा, जिला उदयपुर
जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....47 / 2019.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....उपखण्ड अधिकारी
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुखर्चे.....17.....माह.....07.....2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....23...माह.....01.....सन् 2023 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री अजय सनादय..... मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री कमलेश चौहान
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि..... अपील अपीलान्त
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री
दिनांक 17-07-2019 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....23.....माह.....01.....2023
को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुकमनामा .			3. इजराय हुकमनामा		
4. वकील फीस बाबत ... मीजान			4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।